



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 आषाढ 1939 (श0)

(सं0 पटना 601) पटना, वृहस्पतिवार, 13 जुलाई 2017

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

12 जुलाई 2017

एस0ओ0 113, दिनांक 13 जुलाई 2017—माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा SLP (Criminal) no. 1779/2016 (बिहार राज्य बनाम दिवेश कुमार चौधरी एवं अन्य) में दिनांक 28.02.2017 को पारित आदेश के अनुपालन में बिहार राज्य सरकार, पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से, प्रमादी चावल मिल मालिकों से संबंधितवादों के विचारण हेतु अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी एवं प्रधान दंडाधिकारी, किशोर न्याय पर्षद, (यदि कोई हो), से ठीक बाद के वरीय न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी (असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि), के पाँच (5) न्यायालय अधिसूचित करती है, जो पटना, पूर्णियाँ, दरभंगा, छपरा (सारण) एवं गया (प्रत्येक में एक-एक) में कार्यरत होगा तथा इन पाँच (5) न्यायालयों की अधिकारिता निम्नवत होगी:-

क्र० सं०	न्यायालय	अधिकारिता के जिले
1	2	3
1.	पटना	पटना, वैशाली (हाजीपुर), भोजपुर (आरा), बक्सर, नालंदा (बिहारशरीफ), शेखपुरा, लखीसराय, जमुई एवं बेगूसराय।
2.	पूर्णियाँ	पूर्णियाँ, अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बाँका, खगड़िया एवं मुंगेर।
3.	दरभंगा	दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, सहरसा एवं मधेपुरा।
4.	छपरा (सारण)	सारण (छपरा), सिवान, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) एवं पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)।
5.	गया	गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, रोहतास (सासाराम), कैमूर (भभुआ) एवं अरवल।

2. उपर्युक्त तालिका के कंडिका-3 में यथोलिखित जिलों से संबंधित प्रमादी चावल मिल मालिकों के सभी लंबित वाद, कंडिका-2 में एतद्द्वारा कार्यरत न्यायालय में अंतरित हो जाएँगे।

3. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

(सं0सं0-ए0/एक्ट-1/2017/3862/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा

सरकार के सचिव।

12 जुलाई 2017

एस0ओ0 114, एस0ओ0 113, दिनांक 13 जुलाई 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/एक्ट-1/2017/3862/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा

सरकार के सचिव।

The 12th July 2017

S.O. 113, dated the 13th July 2017—In compliance of the order dated 28.02.2017 passed by Hon'ble Supreme Court, New Delhi, in SLP (Criminal) No.-1779/2016 (State of Bihar Vrs. Divesh Kumar Choudhary & Anr), State Government of Bihar, in consultation with the High Court of Judicature at Patna, notifies five (5) Courts of Senior Judicial Magistrate, 1st class (Civil Judge, Junior Division) next to S.D.J.M and Principal Magistrate, Juvenile Justice Board (if any), which shall be one each in Patna, Purnea, Darbhanga, Saran at Chapra and Gaya for trial of cases filed against the careless rice millers and the Jurisdiction of these five (5) Courts shall be as follows:-

Sr. No.	Courts	District of Jurisdiction
1	2	3
1.	Patna	Patna, Vaishali at Hajipur, Bhojpur at Ara, Buxar, Nalnda at Biharsharif, Sheikhpura, Lakhisarai, Jamui and Begusarai.
2.	Purnea	Purnea, Araria, Kishanganj, Katihar, Bhagalpur, Banka, Khagaria and Munger.
3.	Darbhangha	Darbhangha, Samastipur, Supaul, Madhubani, Sitamarhi, Sheohar, Saharsa and Madhepura.
4.	Saran at Chapra	Saran at Chapra, Siwan, Muzaffarpur, Gopalganj, East Champaran at Motihari, and West Champarna at Bettiah.
5.	Gaya	Gaya, Aurangabad, Nawada, Jehanabad, Rohtas at Sasaram, Kaimur at Bhabhua and Arwal.

2. All the cases pending against the careless rice millers of the districts mentioned in column-3 of aforesaid table, shall be transferred to the Court notified hereby as mentioned in column-2.

3. This notification shall come into force at once.

(F. No. A/Act-1/2017/3862/J.)

By order of the Governor of Bihar,

Surendra Prasad Sharma,

Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 601-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>